



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असामान्य
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 1986/वैशाख 25, 1908
No.185] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 1986/VAISAKHA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मई, 1986

अधिसूचना

का० घा० 260 (घ).—केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि राज्य की सुरक्षा और लोकहित में यह समीचीन नहीं है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० घा० 867 (घ), तारीख 20 नवम्बर, 1984 के अधीन नियुक्त किए गए भारत के उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एम० पी० ठक्कर द्वारा 19 नवम्बर, 1985 और 27 फरवरी, 1986 को सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों लोक सभा के समक्ष रखी जाएं, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त रिपोर्टें लोक सभा के समक्ष नहीं रखी जाएंगी ।

[सं० 1-12014/18/86-आईएस (डिस्क-III)]

एस० एन० गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th May, 1986

NOTIFICATION

S. O. 260 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government, being satisfied that it is not expedient in the interest of the security of the State and in the Public interest to lay before the House of the People the reports submitted to that Government on the 19th November, 1985, and the 27th February, 1986, by Justice M. P. Thakkar, a sitting Judge of the Supreme Court of India, appointed under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S. O. 867(E), dated the 20th November, 1984, hereby notifies that the said reports shall not be laid before the House of the People.

[No. I/12014/18/86-IS (D. III)]

L. N. GUPTA, Addl. Secy.